जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 266 प्रभात चूरू, मंगलवार 24 जनवरी, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बड़ी-बड़ी आंखों वाले, सुस्त, झबरीले और गोल- मटोल पिग्मी लोरिस मूलतः साउथ एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ये जीव पेड़ों से निकलने वाला गम, द्रव, फल व अकशेरुकी जीवों को खाकर अपना सुस्त, निशाचर जीवन बिताते हैं। तथापि, इस सरल रुप व सौम्य लाइफस्टाइल के पीछे इस प्रजाति के अद्भुत व निराले उदविकासी अनुकूलन की कहानी बहुत अहम् है। चीन, डेनमार्क और यू.के. के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन जीवों के कुछ अनूठे अनुकूलनों (अडैप्टेशन) के जैनेटिक आधार का पता लगाने के लिए कई टैस्ट किए। प्रोसीडिंग्स ऑफ नैशनल अकैडमी ऑफ साईन्सेज़ में प्रकाशित इस शोध में कुछ संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि, पिग्मी लोरिस की, लो मैटाबॉलिक रेट, धीमी गति व शीतनिष्क्रियता की क्षमता किस प्रकार विकसित हुई। साऊथ ईस्ट एशिया में मेकॉंग नदी की पूर्व दिशा के जंगलों में रहने वाले इन जीवों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) की रैड लिस्ट में "एन्डेन्जर्ड" वर्ग में रखा गया है। शोधकर्ताओं ने पिग्मी लोरिस के डी.एन.ए. की तुलना गोरिल्ला, ओरागुंटान और गिबन सहित 11 स्तनपायी प्रजातियों से की, प्राइमेट्स के इस असामान्य ग्रुप की बुनियादी उद्विकासी प्रक्रिया को समझने के लिए। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि, जिनोम सीक्वैंस से पिग्मी लोरिस के अनूठे जीव विज्ञान को समझने का अवसर मिला है, वो भी उसे नुकसान पहुंचाए बिना। जैनेटिक टैस्ट से यह भी पता चला कि, पिग्मी लोरिस व कोआला में एक उद्विकासीय समानता है। दोनों में ही एन्ज़ाइम सम्बंधी गतिविधियाँ कम हैं ओर इसीलिए दोनों की मैटाबॉलिक रेट इतनी कम है। यह भी माना गया कि, सरकेडियन रिद्म (शरीर की आंतरिक घड़ी) से सम्बंधित जीन्स के कमजोर होने का सम्बंध लोरिस की शीतनिष्क्रियता की अनूठी क्षमता से हो सकता है। टीम ने उन जीन्स की भी पहचान की जिनकी वजह से ये जानवर बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। पिग्मी लोरिस के डी.एन.ए. की तुलना, टू टोड स्लॉथ से की गई, जो कि अपनी अति धीमी गति के लिए विख्यात है। टीम को दोनों प्रजातियों के बीच समानान्तर उद्विकास के सबूत मिले।

सभी मैडिकल कॉलेजों को कहा गया है कि, प्र.मंत्री का कार्यक्रम "परीक्षा पर चर्चा" सभी विद्यार्थियों को दिखायें

प्र.मंत्री का यह कार्यक्रम 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया है तथा इस आयोजन में प्र.मंत्री 1200 स्कूल के बच्चों से बातचीत करेंगे तथा सवालों के जवाब देंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। चाटुकारिता के एक अनोखे प्रदर्शन के अन्तर्गत, मैडिकल शिक्षा के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च नियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) नैशनल मैडिकल कमीशन ने पूरे देश के मैडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि सभी विद्यार्थी परीक्षाओं से संबंधित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 27 जनवरी के व्याख्यान- "परीक्षा पर चर्चा" को देख-सुन सकें। नैशनल मैडिकल कमीशन के निर्देशों से हतप्रभ कुछ डॉक्टरों ने इस रेग्यूलेटरी बॉडी की प्राथमिकताओं तथा स्वायत्तता पर प्रश्न खड़े किये हैं।

'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, पिछले शुक्रवार को सभी मैडिकल कॉलेजों को भेजे गये एन.एम.सी. के इस सर्कुलर से पहले, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन किया था कि वह सभी मैडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों को निर्देश दे कि वे विद्यार्थियों के लिये इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था करें, तथा (स्वास्थ्य मंत्रालय) इस निवेदन को "सर्वोच्च प्राथमिकता" प्रदान करे।

- पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल स्टूडैंट्स के कई संगठनों ने नैशनल मैडिकल कमीशन (एन.एम.सी.) द्वारा इस बारे में देश के सभी मैडिकल कॉलेजों को पत्र लिखे जाने तथा हिदायत देने पर आपत्ति व्यक्त की।
- इन डॉक्टरों का आरोप है, नैशनल मैडिकल कमीशन, मैडिकल शिक्षा के सुचारू संचालन के लिये गठित सर्वोच्च संस्था है। अतः प्र.मंत्री के कार्यक्रम की पब्लिसिटी करना उसकी प्राथमिकता कैसे हो गयी।
- "कमीशन को तो डॉक्टरों की कमी, मैडिकल एजुकेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत व पर्याप्त बनाने के बारे में सोचना चाहिये।"
- "एन.एम.सी. को इस बात पर दबाव बनाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिये आवंटित बजट में गत तीन साल से जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लगातार कमी क्यों आ रही है।

एन.एम.सी. ने मैडिकल कॉलेजों से यह भी कहा है कि वे "परीक्षा पर चर्चा" कार्यक्रम का "व्यापक प्रचार-प्रसार" करें यह विद्यार्थियों के साथ होने वाले मोदी के संवाद की वार्षिक शृंखला की छठी कड़ी हैं। इन संवादों में, मोदी परीक्षाओं के दबाव से निपटने की टिप्स दिया करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 1200 स्कूली बच्चों के प्रधानमंत्री के साथ संवाद का "लाइव" प्रसारण दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो पर किया जायेगा तथा सरकारी वैबसाइटों एवं सोशल मीडिया पर भी देखा-सुना जा सकेगा।

फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मैडिकल एसोसिएशन (एफ.ए.आई.एम.ए.-फेमा), जो पोस्टग्रेजुएट मैडिकल विद्यार्थियों द्वारा स्थापित संगठन है, के सदस्यों ने एन.एम.पी. के इस सर्कुलर की निन्दा की है तथा कहा है कि रेग्यूलेट्री बॉडी (एन.एम.सी.)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कमियों के बावजूद भी बैस्ट है कोलीजियम सिस्टम'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। जाने-माने न्यायविद् फली एस. नरिमन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति करने वाले कोलीजियम सिस्टम से संबंधित प्रसिद्ध "सैकिण्ड जज" केस वर्ष 1993 में जीता था,

- जाने-माने न्यायविद् फली.एस. नरिमन ने कहा कि, लोकतंत्र में कई कमियाँ हैं पर सभी उपलब्ध सिस्टम्स में यह बैस्ट है, इसी प्रकार कोलीजियम सिस्टम भी सभी उपलब्ध प्रक्रियाओं में बैस्ट है।

लेकिन वर्ष 2010 में आयी अपनी किताब "बिफोर मैमोरी फेड्स" में उन्होंने इस केस को जीतने के लिए खेद जताया। वह कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कोलीजियम सिस्टम में कई कमियां है, फिर भी वह उसे एक बेहतर विकल्प पाते हैं क्योंकि यह एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा तमिलनाडू में अपना स्वयं का टी.वी. चैनल शुरू करेगी

इस चैनल का नाम होगा जनम टी.वी. व संभवतया यह चैनल इस माह ही कार्यरत हो जायेगा

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। सामान्य रूप से पूरे दक्षिणी भारत में तथा विशेष रूप से तमिलनाडु में, मीडिया गेम में पिछड़ते जाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी अपना स्वयं का टी.वी. चैनल शुरु करने की योजना बना रही है, जो राज्य में उसकी आवाज का सहारा बन सके। देश के अन्य भागों के विपरीत, तमिलनाडु के मीडिया को अपने अनुकूल बनाने में भाजपा को बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि तमिल समाचार चैनल पार्टी से ऐसे तीखे और सटीक प्रश्न पूछते हैं, जैसे प्रश्न उससे देश में और कहीं भी नहीं पूछे जाते।

जहाँ तक मुख्यधारा मीडिया कवरेज का संबंध है, भाजपा स्वयं को उपेक्षित तथा बहिष्कृत जैसा महसूस कर रही है, जबकि स्पेस देने के मामले में तमिलनाडु पूरी तरह निष्पक्ष है। लेकिन भारत के अन्य भागों की तरह, मीडिया में उसे तरज़ीह नहीं दी जाती तथा उन मुद्दों को अनावश्यक रूप से नहीं उठाया जाता, जिन पर भाजपा जोर देना चाहती है। इस स्थिति को देखते हुये, भाजपा इसी महीने अपना स्वयं का टी.वी. चैनल शुरु करने की योजना बना रही है। इस चैनल का नाम "जनम टी.वी." होगा। इसी नाम से भाजपा का टी.वी. चैनल केरल में चल रहा है। भाजपा का तमिलनाडु टी.वी. उसी का विस्तार होगा।

मीडिया-दर्शक इससे चौके नहीं हैं। एक मीडिया-हस्ती एवं राजनैतिक विश्लेषक सुमन्त सी रमन ने कहा है: "तमिलनाडु में हर पार्टी का अपना मीडिया चैनल है तथा भाजपा को भी यह जरूरी लग रहा है कि उसका भी अपना टी.वी. चैनल हो, ताकि वह अपनी बात एवं दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा, तमिलनाडु के मुख्यधारा मीडिया का द्रमुक (डी.एम.के.) की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है और इसीलिये भाजपा एक ऐसे चैनल की जरूरत महसूस कर रही है,

- तमिलनाडू में सभी बड़ी पार्टियों का अपना स्वयं का टी.वी. चैनल है। अतः भाजपा इस मामले में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी।
- वैसे भी मेन-लाइन टी.वी. चैनल्स का झुकाव डी.एम.के. की ओर रहता है, अतः अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिये भाजपा को अपने टी.वी. चैनल की कमी महसूस हो रही थी।
- यह भी सच है कि, देश भर में जिस प्रकार का प्रखर कवरेज भाजपा को मिलता है, वह तमिलनाडू में नहीं मिल रहा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को बड़ी राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री तथा नैशनल कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) नेता अनिल देशमुख को दी गई जमानत में कोई भी हस्तक्षेप करने से सोमवार को इंकार कर दिया। ज्ञातव्य है कि सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने बार मालिकों के तुष्टिकरण एवं पुलिस ट्रांसफर एवं पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमन्यम तथा जे.बी. पारदीवाला की बैंच ने सी.बी.आई. द्वारा दायर स्पेशल लीव पीटीशन पर विचार नहीं किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया।

सी.जे.आई. ने शुरुआत में ही, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कह दिया कि पी.एम.एल.ए.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महारानी कॉलेज छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर आर.यू. अध्यक्ष को थप्पड़ मारा

यह थप्पड़ राजस्थान युनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव अरविन्द जाजड़ा ने जड़ा

जयपुर, 23 जनवरी(कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मंच पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष

- घटना के बाद दोनों के समर्थकों के बीच आपस में लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई।
- निर्मल चौधरी ने अरविन्द जाजड़ा के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया अशोक नगर थाने में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महारानी कॉलेज में छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ महासचिव अरिवंद जाजड़ा ने मंच पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को पीछे से थप्पड़ जड़ दिया तथा धक्का मारकर मंच से गिरा दिया। खास बात यह है कि, इस पूरे प्रकरण के दौरान केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद थे।

मीडिया पर बैक डोर सैंसरशिप से बाज आए सरकार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। पत्रकारों की अखिल भारतीय संस्था "द इण्डियन जर्नलिस्ट यूनियन (आई.जे.यू.) ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि वह इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी (आई.टी.) नियमों में संशोधन कर पर्दे के पीछे से

- इण्डियन जर्नलिस्ट यूनियन ने आरोप लगाया कि, सरकार आई.टी. नियमों में संशोधन से ऑन लाइन मीडिया पर सैंसरशिप लगा रही है।

सैंसरशिप थोपने से बाज आए, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ गई है।

यूनियन के अध्यक्ष के. श्रीनिवास रेड्डी और महासचिव बलविन्दर सिंह जम्मू ने एक बयान जारी कर सरकार को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपर लीक हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन

भाजपा व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक मुद्दे पर भारी हंगामा किया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 23 जनवरी। विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत सोमवार को भारी हंगामे के साथ हुई। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोर-शराबे के बीच करीब 10 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा, फिर इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। उधर स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी ने सदन में हंगामा करने और तख्तियां लहराने पर आर.एल.पी. के तीन विधायकों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया।

सोमवार सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने शिक्षक भर्ती पेपर लीक की सी.बी.आई. जांच की मांग करते हुए अपनी बात रखनी चाही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा? राज्यपाल और स्पीकर दोनों ने उनकी बात नजरअंदाज की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) और बीजेपी के विधायकों ने वैल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। रालोपा के विधायकों नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी ने पेपरलीक मामले की सी.बी.आई. जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। राज्यपाल ने करीब 21 मिनट तक विपक्ष के हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ा, लेकिन हंगामे व शोर-शराबे के कारण इसे बीच में ही छोड़ दिया, इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू हुई तब भाजपा विधायक तो चुप बैठ गए, लेकिन रालोपा के तीनों विधायकों ने हंगामा जारी रखा। आर.एल.पी. विधायक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा देवी सी.बी.आई. जांच की मांग वाली तख्तियां सदन में बार-बार लहरा रहे थे।

इस पर स्पीकर डॉ. सी.पी.जोशी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पहले तो तीनों विधायकों को बैठने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो स्पीकर ने तीनों को आज पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। उन्होंने मार्शल को बुलाकर इन विधायकों को सदन से बाहर करने को कहा।

- शोर शराबा इतना ज्यादा था कि, राज्यपाल कलराज मिश्र अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं कर पाए और 10 मिनट बाद ही अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया।
- राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के विधायकों ने वैल में जम कर हंगामा किया, तख्तियाँ लहराईं व पेपर लीक कांड की जांच सी.बी.आई. से कराने की मांग की।
- हंगामे से रूष्ट स्पीकर महोदय, डॉ. सी.पी. जोशी ने तख्तियाँ लहरा रहे विधायकों को दिन भर के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।